THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): He was not making a statement. He just replied to some of the points. Mr. Chidambaram was trying to help you in getting information. It was not a statement at all. He said it is information.

SHRI DIPEN GHOSH: Then what is that? How it is recorded? Let me understand what is that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Listen, Mr. Dipen Ghosh. I allowed you and now you are not allowing me to speak. Please sit down. No, this is not the correct procedure. Mr. Reddy, you please sit down. You see, Mr. Gurudas Das Gupta and Mr. Gurupadaswamy came to me this morning and they wanted to raise this matter. Though it was not on the agenda, they said it was urgent, some lathi charge had taken place, they were women and therefore they said that this matter they should be allowed to raise. I also agreed, "all right, you can raise it for some time" and I allowed them to raise it. They have raised it. They wanted information from the Government and Government has given the information. Even now you want to go on with this. How can it be allowed? You want to change the whole procedure. No, Madam, I allowed you and you had your full say. Whatever you had to say, it was allowed. Now you are again going far beyond the procedure. It is upsetting the procedure of the House. You cannot go on like that. No, Madam, please sit down. It cannot go on record. It cannot go on. Please cooperate. I have cooperated with you; you please cooperate with me. This is going beyond the limit. Please sit down. This is not a debate. There cannot be questions and answers. I allowed you to say whatever you wanted to say. Now it cannot go on like this. Please sit down. Now Mr. Kalpnath Rai.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to ensure remunerative prices to farmers for their agricultual produce and steps taken by Government in this regard

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से किसानों को उनकी कृषि उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता ।

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Madam, the Hon'ble Members have mentioned about "the need to ensure remunerative prices to farmers for their agricultural produce and the steps taken by Government in this regard". As I have stated on earlier occasions in this House the agricultural price policy of the Government is primarily directed towards ensuring remunerative prices to the agricultural producers and safeguarding their interests. In every season, Government announces procurement/minimum support prices of important crops for this purpose keeping in view the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), the views of the State Governments, the concerned Central Ministries and the Planning Commission. The Government, whenever required, undertakes price support operations through public and cooperative agencies.

The recommendations on procurement/minimum support prices are made by the Commission for Agricultural Costs and Prices keeping in view a number of factors, such as, the cost of production of crops, changes in input prices, inter-crop price variations, changes in the "terms of trade" between agricultural and non-agricultural sectors, general economic conditions prevailing in the country, etc.

The cost of production data which are made use of by the Commission are based on comprehensive country-wide studies carried out mostly by agricultural universities in accordance with the concepts, methodology and sampling design worked out by experts. In arriving at cost of production estimates, full account is taken of the value of all inputs, such as, human labour both hired and family, bullock labour, seeds, fertilizers, insecticides, machine labour, irrigation, etc. The cost estimates also take into account depreciation on implements, machinery and farm buildings, interest on working capital and fixed capital, rent of leased land as also imputed rent of owned land and other miscellaneous expenses which the farmer has to incur in his farming operations. As such, the cost of production covers not only paid out costs but also imputed value of owned assets including land and family labour for which the farmers do not incur cash expenses. The CACP duly takes into account any increase in the cost of inputs from year to year while making its price recommendations. While fixing support/procurement prices, it is ensured that these cover cost of production and also provide a reasonable margin of profit to give incentive to farmers for investment and adoption of improved technology.

The Government is fully alive to the needs of the farmers and spares no efforts to see that they receive remunerative prices for their produce.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उसी के संबंध में कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बाढ़ सुखाड़ के कारण हिंदुस्तान के सात लाख गांवों में रहने वाले किसानों की हालत आज ठीक नहीं है, चाहे वह पहाड़ में सेब पैदा करने वाले किसान हों, चाहे बंगाल में जूट पैदा करने वाले वाले किसान हों ...

उपसभापति : कल्पनाथ राय जी आपको टाईम का ख्याल रखना है, क्योंकि इसको जल्दी समाप्त करना है।

श्री कल्पनाथ राय : चाहे गन्ना पैदा करने वाले किसान हों, चाहे कपास पैदा करने वाले महाराष्ट्र के किसान हों, या धान, गेहूं पैदा करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के किसान हों, उनको जो सरकार ने तय किया है, उसके अनुकूल दाम नहीं मिल रहे हैं।

1980 में केन्द्रीय सरकार की कैबिनट ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में यह तय किया कि किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों और कारखानों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दामों में संतुलन स्थापित किया जाएगा। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जो सिद्धांत सरकार ने तय किया, उसके अनुकूल सरकार आचरण नहीं कर रही है। आपको मालूम होगा कि सरकार एडमिनिस्टर्ड प्राइस तय करती है। अब दो साल पहले सरकार ने लोहे का दाम तय किया, रु० 300 क्विंटल से बढ़ाकर लोहे का दाम रु० 600 क्विंटल हो गया, लेकिन आपका गेहूं या धान का दाम अढ़ाई रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ा, तो क्या यह सरकार के सिद्धांत के अनुकूल आता है ?

अब तीन सवाल उठते हैं। एक वह है कि जो किसान के खेतों में चीजें इस्तेमाल होती हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स इनके दाम किस रफ्तार से बढ़े हैं और जो किसान खेतों में पैदा करता है, उसके दाम किस हिसाब से बढ़ा है और जो किसान अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान खरीदता है, उसकी क्या कीमत है ?

मेरा सरकार से कहना है कि जो इनपुट्स खेतों में इस्तेमाल होते हैं, किसानों का आज के पहले खेती में कोई खर्चा नहीं था, वह अपने बैलों से निस्संदेह अपना खेत जोतता था, अपने तालाब से सिचाई करता था, अपने बैल का गोबर खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल करता था और वह फल पैदा करता था। लेकिन आज किसान को फसल पैदा करने के लिए फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल खरीद कर

[श्री कल्पनाथ राय]

करना पड़ता है, ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है, इनसैक्टिसाइड तथापैस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है आज उसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी पैसा देकर करना पड़ता है। इसके साथ ही उसको नहर का पानी या ट्यूबवैल का पानी भी पैसा देकर लेना पड़ता है।

इसी लिए जो एग्रीकल्चर इनपुटस हैं उनके दाम उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गये है, बिजली का दाम भी बढ़ गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है, सरकार ने जो श्रीमती गांधी की अध्यक्षता में सिद्धांत तय किया कि करखानों में पैदा होने वाली वस्तुओं और खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दामों में संतुलन स्थापित किया जाएगा, तो क्या सरकार ने संतुलन स्थापित किया है। जो खेतों में इनपुटस इस्तेमाल होते है, उनके दाम में और जो किसान अपने खेतों में पैदा करता है, उसके दाम में क्या संतुलन है?

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो कारखानों में चीज पैदा होती है, जिसको इस्तेमाल किसान करता है अब तेरह सौ करोड़ रुपये का तेल सरकार विदेशों से मंगवाती है। राजस्थान के गंगानगर में सरसों पैदा हुई। सरकार ने सरसों का दाम 385/–रु० क्विंटल तय किया और किसानों को तीन सौ रूपये क्विंटल भी दाम नहीं मिला। आज बाजार में सरसों का तेल 35 रु० किलों के हिसाब से बिक रहा है जो सरसों किसान ने पैदा की और जो आज बाजार में सरलों का तेल मिल रहा है, दोनों के दामों में क्या कोई सन्तुलन है? किसान आलू पैदा करता है। सरकार किसान से 40 रु० क्विंटल के हिसाब से आलू खरीदती है प्रोक्योरमेंट प्राइस है यानी एक रुपये में ढाई किलो और आलू बाजार में चार रुपये पाच रुपये किलो बिक रहा है तो जिस किसान ने आलू पैदा किया वह भी मारा गया और जिसने आलू को खरीदा उसको भी बहुत महंगे दाम पर वह मिला। इसलिए जो पैदा करने वाला किसान है उसको भी उचित मूल्य नहीं मिलता और जो उस आलू का उपभोग करता है उसको भी बहुत महंगें दाम पर आलू मिलता है उसमें बिचोलिए करोड़ें रुपये खा रहे हैं। मैंने उदाहरण के लिए सरसों के तेल का उदाहरण रखा और आपके सामने आलू का उदाहरण भी रखा। इस प्रकार किसान जिन चीजों को खेतों में पैदा करता है उनका दाम बहुत सस्ता और जो उन चीजों का उपभोग करता है उसको वे चीजें बहुत महग दाम पर खरीदनी पड़ती है और बीच का सारा मनाफा बिचौलिये ले जाते हैं माननीय उपसभापति महोदया, सरकार ने यह तय किया और 1984 में राजीव गांधी जी ने जो कि हमारे प्रधान मंत्री हैं उन्होंने बम्बई में एक सभा में कहा कि अब तक तो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन दाम तय करता था लेकिन अब एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन होगा जिसके करीब 7 सदस्य होंगे, जिसमें उपभोक्ता के, उत्पादन करने वाले के उत्तर, दक्षिण के, पूर्व के, पश्चिम के, ड्राई लैंड के, वैट लैंड के लेबरर्ज के सब के प्रतिनिधि होंगे पहले कास्टिंग होगी और तब प्राईसिंग होगी। उप सभापति महोदया, दिसम्बर, 1984 में प्रधान मंत्री ने एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन बनाने की घोषणा की और 1985 में सदन के अन्दर कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह ने घोषणा की थी कि एक महीने के अन्दर एग्रीकल्चरल कास्ट एड प्राईज कमीशन बनायेगा। फिर 1986 में सरकार ने इसी सदन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जबाब में कहा कि एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन बन जायेगा। अब 1987 है और आज तक एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन की जो पूरी मैम्बरशिप है उसको नोमीनेट नहीं किया गया और एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन नहीं बना। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन को आप अपने वक्तव्य में एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन कहते हैं और चार वर्षों में आपने यह प्राइस कमीशन नहीं बनाया। यहां कृषि मंत्रालय में हजारों कर्मचारी है सैक्रेटरी है ज्वाइंट सैक्रेटरी है और पता नहीं कौन-कौन है लेकिन आज तक वह एग्रीकल्चरल कास्ट

एंड प्राइस कमीशन जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने की थी, चार-चार वर्षों बाद भी नहीं बनाया। यदि यह कमीशन नहीं बनाया तो फिर आप किसान के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के उचित दाम कैसे तय करेंगे। देश के अन्दर बाढ़ और सुखाढ़ है और यहां सौ वर्ष के अन्दर देश में सब से भयानक सूखा पड़ा हुआ है देश के कुछ इलाकों में जो बाढ़ आई है।

उपसभापति : समाप्त कीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : और अधिकांश लाकों में सूखा पड़ा हुआ है। जब किसान बैंक से कर्ज लेकर कोआपरेटिव से कर्ज लेकर फर्टिलाइजर खरीदता है, ट्रैक्टर का पैसा देता है पेस्टीसाइड्स और इन्सैक्टीसाइड्स का इस्तेमाल करता है, बाढ़ आई तो फसल नष्ट हो गई और सूखा आया तो फसल नष्ट हो गई। परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों के किसान आज 99 फीसद किसान कर्ज से लदे हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल के ऊपर आप गंभीरता से विचार करें। आदरणीय उपसभापति महोदया, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लिखा हुआ है कि हम उत्पादन उत्पादकता और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं निवेदन करना चाहता हूं कृषि महोदय से कि आठवी पंचवर्षीय योजना जो सरकार बनाने जा रही है उस योजना में यदि सरकार ने गारन्टी बिजली और गारन्टी खेतों को पानी देने की व्यवस्था नहीं की तो जो हमारा हिन्दुस्तान आज खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर है आने वाले जमाने में उसे बहुत बड़े संकट का मुकाबला करना पड़ेगा।

आदरणीय उपसभापति महोदया, आखिरी बात कहना चाहूंगा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कारखानों में बनने वाली वस्तुओं के दामों में 300 गुना की बढ़ोतरी हुई है जबकि किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों में 9 प्रतिशत की भी वृद्धि नहीं हुई है। जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उसका भी सरकार अध्ययन करे और यह जो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आयी है, इसका भी अध्ययन करे।

आदरणीय उपसभापति महोदया आज हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि देश के करोड़ों-करोड़ किसानों के पेट का जहां सवाल है बाढ़ और सुखाढ़ से सारा देश त्रस्त है वहीं हमारे कुछ जनघाती और राष्ट्रघाती लोग जो जनतंत्र की जगह राजतंत्र लाना चाहते हैं और जिन्होंने अपने जमाने में अपनी हुकूमत के दौरान किसानों को केवल बर्बाद किया, उन्हें हिन्दुस्तान के इन करोड़ों किसानों के पेट से बाढ़ और सुखाढ़ से कोई रिश्ता नहीं है बल्कि किसी की चरित्र-हत्या को ही राजनीति की रानी समझते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हर चीजों के दाम बढ़े हैं तो सरकार की अपनी ही जो उसकी नीति है उसके अनुसार किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दामों ... (समय की घंटी)।

एक बात आखिरी कहकर खत्म करूंगा। आदरणीय उपसभापति महोदया भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ ने एक प्रस्ताव जो प्रसारित की है उसके अनुसार :—

"Prices of Farm Inputs: Prices of farm inputs have gone high in comparison to the prices of farm produce received by the farmer in the market. Farm inputs be declared essential commodity and a separate Agricultural Inputs Prices Commission be set up to fix and regulate their prices.

Survey on Agricultural Price Parity: Recently Prof. Swami and Dr. Gulati of Delhi University have surveyed the price parity of farm produce and farm inputs since 1971 to 1981, and declared, thousands of crores of rupees loss to Indian farmer. Convention appreciates their efforts and asks the Government to now take decision in favour of the farmers and fix remunerative prices so that further loss may not be incurred to Indian Farmer."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please excuse me, I cannot allow you to go like that.

SHRI KALPNATH RAI: I will take only one minute.

"Treat Agriculture as Industry: Convention asks Government that agriculture be declared as an Industry.

National Agro-Industries policy be made and all facilities extended to industries be extended to agriculture also."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अपनी ही नीति के अनुकूल अपने किसानों को रेमुनरेटिव प्राइस दे तो हिन्दुस्तान के किसान जहां आत्मनिर्भर बने वहीं हमारा देश शक्तिशाली बनेगा ।

SHRI DARBARA SINGH (Punjab): May I draw the attention of the hon. Minister to the second para of his statement?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can ask it afterwards. Not now.

SHRI DARBARA SINGH: He has to reply to that point.

उपसभापति : अच्छा बताइये ।

SHRI DARBARA SINGH: The Minister has said that the minimum support price is made by the C.A.C.P. keeping in view the cost of production of crops, changes in input prices, inter-crop price variations, changes in the "terms of trade" between agricultural and non-agricultural sectors. Will he kindly explain this point in detail?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Chitta Basu. Absent. Shri Ram Chandra Vikal.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया,... **(व्यवधान)** ...

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : माननीया यहां पर ऐसा नहीं है । यह तो गलत परम्परा है... **(व्यवधान)**...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीया, नाम तो सबके हैं । पार्टीवाइज नाम आने चाहिये... **(व्यवधान)**.. विकल जी मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं जो व्यवस्था डाली है वह गलत हो जायेगी ।

उपसभापति : आप बराबर कह रहे हैं । लेकिन अभी अरेंजमेंट ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य ज्यादा हैं इस लिये उनकी तरफ से दो लेने हैं और फिर आपका है क... **(व्यवधान)** ...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : तो बाद में दे दीजिये इन्हें ।

उपसभापति : आप बाद में बोलेंगे विकल जी ?

श्री राम चन्द्र विकल : मुझे क बजे मीटिंग में जाना है ।

उपसभापति : एक बजे मीटिंग में जाना है इन्हें तो बोलने दीजिये ।

श्री राम चन्द्र विकल : माननीय उपसभापति महोदया, पिछले सप्ताह प्रश्नकाल में माननीय कृषि मंत्री जी से सवाल हो रहा था कि किसानों को उनकी लागत और मेहनत के मुताबिक दाम मिल रहे हैं या नहीं ? यह सवाल भी था कि जो कृषि लागत मूल्य आयोग बना है उसके कौन-कौन से मेंबर हैं ? उसने क्या सिफारिशें की हैं । उस सवाल से उस दिन यह संतुष्टि नहीं हो रही कि कृषि लागत मूल्य आयोग के मेंबर कौन कौन हैं और उन्होंने कब-कब रिपोर्ट दी है । उसके बाद यह आधे घंटे की चर्चा बढ़कर ध्यानाकर्षण पर चली गयी । आज भी मंत्री महोदय ने जो अपना वक्तव्य दिया है उससे यह जाहिर नहीं होता कि किसान को उसकी लागत के मुताबिक दाम मिल रहे हैं या नहीं ? उपसभापति महोदया, मैं गांव का आदमी हूं, गांव की बातें जानता हूं कि हाला का पेट हीले

[श्री रामचन्द्र विकल]

से नहीं भरता । यह हमारे गांव की कहावत है । जो हल चलाता है उसका पेट अच्छी-अच्छी बातों से नहीं भरता । मंत्री जी का वक्तव्य तो सारगर्भित है, लेकिन उससे वह मामला हल नहीं हुआ जो यह सदन चाहता है । सच्चाई यह है कि किसान उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है । पैदा भी करता है और खरीदता भी है । इस देश का दुर्भाग्य यह है कि किसान को उत्पादक समझा जा रहा है, वह उपभोक्ता भी है, यह नहीं समझा जा रहा है । मैं किसान की हालत जानता हूं । एक-दो फीसदी किसानों को छोड़कर 98 फीसदी किसान, जोकि गरीब होता है, वह मजबूरी में कर्जा चुकाने के लिए बिना भाव अपनी फसल को बेचने को मजबूर होता है । वह एक महीने बाद हर चीज खरीदना शुरू कर देता है । जो उसकी खरीद की चीजें हैं, वह ज्यादा मंहगी हैं और जो वह बेचता है वह सस्ता है । दूसरे आज कल्पनाथ राय जी ने चर्चा की और कृषि मंत्री जी भी जानते हैं कि आज खेती व्यापारिक दृष्टि से हो रही है । आज चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे खेत हो, चाहे सिचाई हो, चाहे बिजली हो, चाहे मजदूर हों--ये सब मंहगे हो गए हैं । लेकिन उसकी लागत के दाम उसे नहीं मिल रहे हैं । मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कृषि लागत मूल्य आयोग बनाया कि नहीं ।

श्री कल्पनाथ राय : नहीं बनाया ।

श्री राम चन्द्र विकल : आपका जोश तो ठीक है कल्पनाथ जी, लेकिन जोश में मुझे भी अपनी बात कह लेने दो । मैं उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने उस दिन सवाल के जवाब में कहा कि कृषि लागत मूल्य आयोग बन गया है । उसने सिफारिशें की हैं और उसके मुताबिक हम दाम दे रहे हैं । यह कई बार कहा है । आज मैं पुनः जानना चाहता हूं कि कृषि लागत मूल्य आयोग कब बना है ? उसके मेंबर कौन-कौन हैं ? उसकी क्या-क्या सिफारिशें हैं और कब-कब की हैं और उसके मुताबिक उसे गेहूं, गन्ना, जूट, नारियल, कपास, सब्जी--जो भी किसान पैदा करता है, आपने कौनसी कीमतें दी हैं । उपसभापति महोदया, मुझे मालूम है किसान का बच्चा, उसका बाप चौबीस घंटे, दिन-रात, उनका कोई टाइम नहीं है, मेहनत करते हैं और किसान भी चौबीस घंटे लगा रहता है । फिर चाहे वह हरित क्रांति कर दे, श्वेत क्रांति कर दे--जब भी किसान पैदावार बढ़ाएगा, होना तो यह चाहिए कि उसको इनाम दिया जाये, पारितोषिक दिया जाये । उल्टा यह जुर्माना होता है उन पर अगर उन्होंने अधिक पैदा किया क्योंकि इससे कीमतें गिर जाती हैं और किसान निराश हो जाता है । फिर वह पैदावार करने के लिए उत्साहित नहीं होता । मैं चाहूंगा कि अगर देश की पैदावार बढ़ानी है, जैसा मंत्री जी ने कहा कि दूध की पैदावार बढ़ानी है या सबको दूध देना है तो उससे बनने वाली चीजों पर आपने पाबंदी लगा रखी है, मैं उस पर बाद में कभी कहूंगा, लेकिन आप पीने का पानी भी हैं नहीं दे रहे हैं तो दूध कहां से देंगे ? सारी जिम्मेदारी सरकार लेती जाएगी और उसको नहीं निभा पाएगी तो उसका कारण यही है कि किसान व मजदूर जो है वह बड़ी मात्रा में पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता । समाज में उसको आदर नहीं मिलता । उसको आदर और साधन आप दें तो वह भूखे रहकर भी उत्पादन कर सकता है । लेकिन जो जगह बदलने वाला व्यापारी है, जो शक्ल बदलता है उसका मुनाफा कहीं ज्यादा है बजाय उसके जो पैदा करता है चीजों को । यदि आप उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़ाते हैं तो फिर किसान को हतोत्साहित करते हैं उत्पादन करने के लिए । यदि आप उसको उचित दाम दें, उसको समाज तक सम्मान दें, तो मैं समझता हूं कि देश की पैदावार बढ़ेगी और हरित क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति किसान देश में ला सकेगा । इसके साथ ही मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि आप जो मूल्य निर्धारित करते हैं, जो लागत किसान की निर्धारित करते हैं वह आप कैसे करते हैं ? किसान की जो लागत है उसके आधार

पर करते हैं तो उसके लिए जो आप कृषि मूल्य लागत आयोग या कमेटी बनाने जा रहे हैं उसमें आप किसानों को उचित दाम दिलाएं तभी देश समृद्ध हो सकता है और अनाज की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

उपसभापति : मैं चाहती हूं कि यदि आप लंच ब्रेक न लें तो सभी लोग इस पर बोल सकते हैं। आप लोग केवल 5 मिनट लें ताकि हम इसको लंच टाइम तक पूरा कर सकें।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Madam, may I make a submission? We can sit for half an hour more and give a break, lunch break.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is up to the Members. If you finish within the time allotted, we can have. I have nothing to say.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: It is not possible. There are a number of Members.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is why I said that. Let the Members speak. The lunch break will not be there.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उपसभापति महोदया, किसान की बारी आते आते समय की भी गति रुक जाती है और भोजन की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लगता है कि किसान की वस्तुस्थिति का चित्रन इन दो बातों से ही हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हर खेत को पानी दे दें, वह हर हाथ को काम दे देगी और हर मुंह को खाने को भी देगी। इस मूल आधार को भारत सरकार अगर मान ले और कारगर ढंग से उसके लि काम करे तो इसका निराकरण हो सकता है।

महोदया, किसान के उपज मूल्यों पर भाषण बहुत हो सकता है, लेकिन समय की सीमा देखकर मैं कुछ तथ्य के प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय रामचन्द्र विकल जी ने भी कहा है कि कृषि मूल्य आयोग में जो संख्या बढ़ाई गई है उसमें क्या नए सदस्यों का समावेश कर लिया गया है? अगर कर लिया गया है तो जिनका समावेश किया गया है वे किसके प्रतिनिधि हैं? बड़े किसानों के, मध्यम किसानों के या छोटे किसानों के प्रतिनिधि हैं? क्या वे बटाईदारों का या मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं? अगर समावेश नहीं किया गया है तो उनका कब तक समावेश किया जाएगा और उनका उपयोग किया जाएगा?

महोदया, मूल्य निर्धारण की बात पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहना चाहता हूं? मूल्य निर्धारण का मापदंड पंजाब के किसानों की उपज है या बिहार के जहां एक फसल होती है और वह भी कम होती है? तो मूल्य निर्धारण किसके ऊपर है? मुझे पता है कृषि सलाहकार समिति में एक बार पूर्व कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी तो मूल्य निर्धारण करने वाले अध्यक्ष भी बैठे थे और उसमें बहस के अंत में उन्होंने कहा कि आपको जितनी बहस करनी हो कर लो, मूल्य निर्धारण की जिम्मेदारी तो हमारी है, हम करेंगे। उस समय मैंने इस बात को उठाया था कि अगर मूल्य निर्धारण इन्हीं को करना है तो हम लोगों का यहां पर विचार करने की क्या जरूरत है? इस तरह की बैठक और इस तरह की बात यहां पर क्यों हो। मैं समझता हूं मंत्री महोदय उस समय भी चुप रह गये और आज भी इसके लिए चुप हैं। मंत्री जी ने कहा था कि मूल्य निर्धारण के पहले जो सदस्य गण हैं और विधायक हैं उनसे मिल लेंगे जगह-जगह पर। लेकिन आज तक इन्होंने मिलने का कोई प्रयास नहीं किया और मंत्री जी के सचिवालय में इस ओर ध्यान भी नहीं दिया गया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कृषि मूल्यों की बात कही जाती है तो सीधी बात अनाज पर चली जाती है, जो किसान उत्पादन करता है उस पर चली जाती है। इससे लगता है मूल्य में

[श्री जगम्दबी प्रसाद यादव]

कुछ बात बढ़ रही है। लेकिन मूल्य निर्धारण कुछ और देशों में भी होता है। उसका उदाहरण भी लेना पड़ेगा तभी शायद कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय और समाज को उसमें करने में सहायता मिलेगी। जापान खेती करता है वहां पर 7 परसेंट लोग खेती करते हैं वहां पर दो तरह के कृषि मूल्य दिये जाते हैं। एक तो उन को स्प्रिंकलर वाटर भी अनुदान में दिया जाता है। दूसरी तरफ उनकी चीजों की कीमतें इस प्रकार से रखी जाती है कि किसान उन चीजों को आसानी से उठा सके। वहां पर एक तरबूज 100 रुपये से ऊपर है, एक खरबूजा 35 रुपये से ऊपर है और सेब और नारंगी 5 से 10 रुपये है। घर बैठे किसान को मिल जाता है। विकल जी कहते हैं कि किसानों को पानी अनुदान में मिलना चाहिए और फिर पानी से बनने वाली जो बिजली है, मैं यह कहता हूं कि इसके लिए अनुदान की बात तो अलग, उनको बराबर बिजली मिलती रहे इसकी व्यवस्था आप कर दीजिए। उसके बाद खाद की व्यवस्था कीजिए। जब आप कहते हैं कि किसानों के मूल्य में वृद्धि हुई तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज से 5 वर्ष पहले जिस गति से खाद की उपयोगिता किसानों ने शुरू की थी आज उस गति में कितना धीमापन आ गया? आप कहते हैं कि खाद का खर्च बढ़ा है। बढ़ा इसलिए है कि सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ने के कारण खाद की कुछ बिक्री बढ़ी है लेकिन खाद की जिस गति से वृद्धि होनी चाहिए थी उस गति से नहीं हुई। आप कितने प्रति किलो प्रति हेक्टेयर में देते हैं उस दृष्टि से जापान और दूसरे विकसित देश जो कृषि में विकसित नहीं माने जा सकते उद्योग में भले ही विकसित हैं, लेकिन खाद के मामले में हमारी उनकी पैरिटी नहीं है। जब तक उस पैरिटी में नहीं जाते तब तक किसान के उत्पादन की बात किस तरह से करते हैं इस बात के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान का 90 लाख परिवार है और 90 लाख परिवार में से 65 लाख परिवार छोटे किसान का है जिसके जिम्मे 75 परसेंट जमीन है। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नीति में छोटे किसानों के उत्पादन के सामान की बिक्री की क्या व्यवस्था की है? मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि छोटे किसान, बटाईदार, खेतिहर मजदूर जो हैं, वे भी अनाज बेचते हैं कपड़े के लिए, कर्ज के लिए, दवा के लिए लेकिन कभी आप कल्पना नहीं कर सकते वे छोटे किसान, बटाईदार और सीमान्त किसान किस तरह से लूटे जाते हैं। उनको किसी भी कीमत पर बिचौलिये बाजार से ज्यादा कीमत नहीं देते। भारत सरकार की जब तक कोई व्यवस्था सहकारिता के रूप में नहीं होगी तब तक छोटे किसान के लिए, सीमान्त किसान के लिए बड़ी मुश्किल है। न किसानों के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वे इस सामान को रख कर कीमत अधिक ले सकें। हमारे देश में जो किसान

1.00 P.M.

परिवार हैं, जो सीमान्त किसान है, उनकी बटाईदारों की क्या स्थिति है, इस पर विचार करने की जरूरत है।

उपसभापति : बोलने वाले 10 सदस्य है, इसलिए आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सरकार ने पुस्तक प्रकाशित की है उसमें चार चीजें दी हैं। उचित भूमि, जल और उत्पादन के अन्य स्रोत, जीवन स्तर का खर्चा और कृषि पर होने वाला खर्चा, ये चार तत्व आपने बताये हैं। अगर इन बातों का सही रूप में विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि किसानों की हमारे देश में आज क्या हालत है।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि रेफरेन्स के तौर पर श्री कल्प नाथ राय जी ने उसका जिक्र किया है, किसान जो चीजें पैदा

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

करता है और जो चीजें वह उपभोग में लाता है, उनकी कीमत क्या है? अगर आप इसको अच्छी तरह देखें तो पता चलेगा कि किसान जो चीजें पैदा करता है उनकी कीमत तो कम होती है और जो चीजें वह उपयोग में लाता है उनके दाम उसको ज्यादा देने पड़ते हैं। मेरे पास एक चार्ट है, उससे यह पता चल जाएगा कि चीजों के दामों में कितना अन्तर है। जिन सभी चीजों की कीमत पहले से 22 प्रतिशत बढ़ी है उनके दाम, कुछ की 67 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। मसाले की कीमत में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाने के तेल में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दालों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गुड़ में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धनिये की कीमत में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लहसुन में 325.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लाल मिर्च में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरसों के तेल में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तिल के तेल में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मूंगफली के तेल में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से आप देखें तो किसानों पर महंगाई का भार बहुत बढ़ गया है। किसान जो चीजें बेचता है उसकी कीमत तो कम होती है और वही चीजें जब उसे बाजार से खरीदनी पड़ती हैं तो उनके दाम ज्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? खाद की बात मैं आपसे कह चुका हूं। आपने किसान द्वारा पैदा की जाने वाली चीजों के दाम तो निश्चित कर दिये, लेकिन कारखानों में जो चीजें पैदा होती हैं उनके दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

जब किसानों की बात आती है और उनकी चीजों के दाम निश्चित करने की बात आती है तो आप उपभोक्ता को भी साथ ले लेते हैं। जब किसानों द्वारा उत्पन्न करने वाली चीजों के दाम निश्चित करते समय उपभोक्ताओं का ध्यान रखते हैं तो उसी तरह से कारखानों में जो चीजें पैदा की जाती हैं उनके दाम निश्चित करते समय भी उपभोक्ताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। श्री कल्प नाथ राय जी ने इनपुट्स की बात कही। पहले जिस पावर टिलर ट्रैक्टर के दाम 12 हजार रुपये थे अब उसके दाम 32 हजार और 40 हजार तक हो गये हैं। ऐसी हालत में गरीब किसान कैसे ट्रैक्टर खरीद सकता है। मैंने कृषि मंत्रालय को जब इस संबंध में लिखा तो मुझे कहा गया कि आप वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखिये। मैंने तीनों मंत्रालयों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। अगर छोटे किसानों के लिए कोई रियायत दी जाएगी तो उसका फायदा बड़े किसान उठा लेंगे। उनका यह भी कहना था कि जो भी सुविधा छोटे किसानों को दी जाती है उसका फायदा बड़े किसान उठा लेते हैं। इसलिए यह संभव नहीं है। पंचवर्षीय योजनाओं में हमने देखा जो पैसा गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए वह उन तक नहीं पहुंच पाता है। यह ठीक है कि आपके पास साधन नहीं हैं, लेकिन जो भी साधन हैं उनको आम लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए जिससे गरीब लोगों को उनका फायदा पहुंच सके। राज्य सरकारें राज्यों में हैं और एक दर्जन से अधिक अधिकारी भी जिलों में किसानों के लिए रखे गये हैं, लेकिन वे किसानों के मालिक हैं, किसानों के सहयोगी नहीं हैं। मैं परसों भी आपसे बात कर रहा था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने बहुत बड़ी हरित क्रांति की इसके नंगाड़े पीटे जाते हैं लेकिन हरित क्रांति किसने की? साधनों ने, बौरलोग के बीज, व्हीट के बीज और मैज के बीजों के ब्रेक थ्रू ने। आज भी एक चुनौती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सामने है। आज भी दलहन और तिलहन की नितांत कमी है। उस

कमी को पूरा करने के लिये इन बीजों का ब्रेक थ्रू करने की आवश्यकता है। आज श्वेत क्रांति की बात कही जाती है। मुझे आश्चर्य होता है कि आज कृषि मंत्रालय 75 करोड़ रुपये का बटर आयल, घी और दूध लाकर शहरों में बांट देता है। आज भी दिल्ली मे 9 लाख लीटर इसका दूध बांटते हैं और इस तरह आप श्वेत क्रांति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन गरीब किसानों को जो दूसरा प्राइस मिलना चाहिए वह है उनके मवेशी। मुझे कृषि मंत्रालय बता दे कि इन 65 लाख छोटे परिवारों को आपने कौन से अच्छे नस्ल के मवेशी दिये हैं ताकि वे उनकी जीविका का सहारा बन सकें। मुझे इस बात की तकलीफ है कि गैंजेटिक प्लेन में रहने वाले जो किसान हैं इन किसानों की फसल हर साल डूब जाती है, खेत कटते हैं, मिटते हैं बाढ़ से। इसके लिये मैं चाहूंगा कि कोई भी योजना, जो कि इस समय न योजना मंत्रालय में हैं और न कृषि मंत्रालय में, वे सिर्फ प्राइस की बात करेंगे। प्राइस की बात आप उससे करें जो प्राइस लेने की शक्ति रखता हो, जो अपनी पैदावार को रखकर प्राइस रख सके लेकिन सरकार इस बारे में बात नहीं करती है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री० हेच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए]

मैं दूसरी बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि कृषि का उचित प्राइस मिल सकता है अगर आप क्राप प्लानिंग करें। आज तक क्राप प्लानिंग नहीं हुई है। इसके न होने के कारण किसान को यह पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज वह पैदा करे जिससे उसको अधिक दाम मिले। इसलिये इसकी व्यवस्था होना आवश्यक है।

आपने जो इंश्योरेंस की बात की है वह इंश्योरेंस आप कहां डाल रहे हैं। वह किसानों तक पहुंचा है क्या? वह किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। प्राइस देने की व्यवस्था जो है, लाभकारी प्राइस सब किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्राप प्लानिंग की व्यवस्था आप कब तक कर पाएंगे?

दूसरी बात जो किसानों के संबंध में है वह यह है कि जब तक किसानों को कृषि का मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया जायेगा तब तक उनको उसकी ठीक से जानकारी नहीं हो पायेगी। किसान कौन सा अनाज बोये, कौन सा प्लान्ट लगाये, कैसे लगाये जमीन की मिट्टी क्या कहती है कितनी खाद मांगती है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। गैंजेटिक प्लेन में मिट्टी में जिंक की कमी के कारण 30 प्रतिशत फसल मारी जाती है। यदि उनको बता दें तो उनको पूरी फसल मिल सकती है। लेकिन वहां पर जिंक फर्टिलाइजर की व्यवस्था नहीं है और किसान जानता भी नहीं है और वह उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जब मैनेजमेंट की बात हमने अनेक किसानों से पूछी तो उन्होंने कहा कि कृषि मैनेजमेंट की आज नितान्त आवश्यकता है। अगर बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई हो सकती है, उद्योग और बिजनेस मैनेजमेंट को लोग पढ़ सकते हैं तो कृषि मैनेजमेंट को क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं कृषि मंत्री जी से...

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): अब आप खत्म कीजिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।

यदि सचमुच में आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो किसानों की श्रेणियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर पंजाब का किसान अपने खेतों में खाद देगा तो वह तीन फसल लेगा। लेकिन अगर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा का किसान एक बार अपने खेतों में खाद देगा तो वह एक ही फसल लेगा।

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

खाद भी तभी दे सकेगा अगर पानी है अगर पानी नहीं है तो वह खाद भी नहीं दे सकेगा। तो इसको देखते हुए आप किसानों की चीजों की कीमत कैसे तय करेंगे ? एक जगह के किसान के लिये कोई मूल्य लाभकारी हो सकते हैं लेकिन वही दूसरे के लिये लाभकारी नहीं हो सकते । तो ये चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है । तो इसमें ऐसे लोगों को जिनको इसकी अनुभूति है, इसकी जानकारी है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ेंगे या फिर एयर कंडीशन्ड में रहने वाले जो किताब के द्वारा किसान को पढ़ने वाले हैं, किताब के द्वारा मूल्य निर्धारण करने वाले हैं, जो आज तक करते आ रहे हैं इसमें उनको ही जोड़ेंगे क्या ? इसलिए मैंने पहले सवाल आप से पूछा था कि आयोग में किसानों के प्रतिनिधि बड़े, छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के प्रतिनिधि जोड़े जाएं अगर इन के प्रतिनिधियों को उस में जोड़ पाते हैं तो कुछ कर पाएंगे अन्यथा नहीं इस एयर कंडीशंड से निकलने के बाद वे किसी कृषि यूनीवर्सिटी में एयर कंडीशंड में चले जाएंगे । इसलिए मैं कहता हूं कि आई०सी०ए०आर० का विद्वान आज भी गांव में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, किसी के साथ गांव में रहने के लिए तैयार नहीं हैं, किसान को समझने के लिए तैयार नहीं है और किसान भी उस विद्वान को समझने में असमर्थ हो जाता है । इन दोनों में इस तरह से समन्वय नहीं हो पाता है । मान्यवर, जब तक इन दोनों का समन्वय और कृषि मूल्य आयोग का किसानों के साथ समन्वय नहीं होगा किसानों को अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल सकेगा । इसलिए मैं समझता हूं कृषि मंत्री जी इस पर प्रकाश ही नहीं डालेंगे बल्कि व्यवस्था भी डालेंगे जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें ।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome this short debate on agricultural prices. We have been debating this issue ever since Parliament came into existence, since 1952. In the past we had the farmers' forum of Members of Parliament. Even now Members of Parliament participate in organised groups and they work as lobbies for farming community in the country. In spite of the movement of farmers and farming community since long it is not strong enough to build its pressure on the policy-makers either at the Central level or at the State level. The problem of the farmer remains where it was since Independence. The problem is that the farmer gets very little to what he produces but he has to pay very high for what he purchases. Another phenomenon is that there is no parity—why parity?—there is no rational link between the prices of agricultural commodities, particularly the prices of food articles and the industrial goods or industrial commodities. There is also another phenomenon. There is no rational link or relationship between different agricultural commodities also in respect of prices. These are all various anomalies. For lack of time I cannot go into all these things. But I only point out that there is a failure of the Government in formulating a credible policy, an effective policy to bring justice to the farmer. The economy of the country depends upon the farmer. We have been saying it but we have been neglecting it. The backbone of the country is the farmer. So the farming community should get justice for the labours that it puts in. The various evaluations and assessments in regard to the cost and price that have been gone into somehow seem to have no relevance to the conditions of the farmer. If the rural sector where the majority of the people live and where the farming community dominate does not get justice at the hands of the Government, the overall economy will not grow.

Sir, we are in the Seventh Plan. According to indications, the Seventh Plan growth in agriculture may not exceed 3.5 per cent or 4 per cent, whatever may be our ambitions. The

main reason is that the farmers are not getting proper incentives at the hands of the Government. Government may be saying that they have been adopting a package of measures, subsidy in fertilizers, subsidy in electric power and fixation of support prices and purchase prices. All these things, the whole package of measures that the Government has been adopting from time to time has not solved the problem of the farmer. That is a fact of life. Therefore, I feel that the Government is oriented towards industry and big industry. Industry should grow. I am not against industry. But agriculture should not be neglected, which is the bedrock for industry and industrial growth. Agriculture supplies raw materials for industries. Therefore, the Government of India should reorient its policies towards agriculture and they should not regard some of the assistance or help they give as generosity bestowed on agriculturists. It is their duty to do that. The economy of the country cannot be strengthened, broadened, consolidated unless and until the rural sector is strengthened and in the rural sector farmers get justice, proper return for the produce they give to the market.

Having said that, since I have no time, I will take up one small issue, the dairy industry in India. Dairy is very important. It is an important activity. Milk is required for all people, especially for children. And we have been importing dairy products from EEC countries, as my friend is aware. We want the dairy industry to grow. It should be a subsidiary industry for agriculturists. But of late, I am told—if I am wrong, I must be corrected by the Minister—some big multinationals are trying to persuade EEC countries not to give aid in regard to dairy products to India. The reasons given by them are very very strange. There is an organisation, called the Netherlands Committee of India; I do no know the background of this organisation.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : I can give you.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : I want the Minister to enlighten us about it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Better if you raise it when we discuss...

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I am not speaking; that is why I am taking this opportunity and I want you to enlighten us as to what is the background of this organisation. They seem to be carrying on a campaign that the EEC countries should not give aid to India in respect of dairy products. They want to phase out this aid to India within two years. They do not want dairy aid to India for bottle feeding; they do not want aid for exotic cross-breeding either, imports from India to the EEC countries. And in this, Unilever, a multinational company is at the back. Hindustan Lever is working on this. The main purpose is with a view to make India self reliant in respect of dairy products. They would like EEC countries to stop aid in this area. I would like my friend to enlighten us about this and what is the nefarious design behind it. I would like him to take suitable steps, appropriate steps, if he finds anything wrong committed by Hindustan Lever or Uniliver in this regard, and expose the machinations of Netherlands Committee of India which is carrying on this campaign in the EEC countries.

Finally,—I digressed somewhat, but it is relevant to agricultural development in India, because milk and milk products are very important; dairy is very important—I want that the Government of India should constitute a committee to evolve a policy of parity in prices between the agricultural commodities and industrial commodities, and a parity between agricultural commodities themselves. Without stabilisation of prices in agricultural commodities, without adequate return for the agricultural produce, I am afraid, the economy of

rural India will suffer and thereby the economy of the country itself is going to suffer.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shri Ghulam Rasool Matto. He is not here. Shri Vincent. He is not here. Shrimati Bijoya Chakravarty. She is not here. Shri Ram Awadhesh Singh.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने पुराने साथी कल्पनाथ राय जी को धन्यवाद करना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : नहीं-नहीं, धन्यवाद में ही टाइम निकल जायेगा ।

श्री राम अवधेश सिंह : इन्होंने इनीशियेटिव लिया और यह कालिंग अटैंशन के लिए दस्तखत कराया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में बहस हो रही है । महोदय, यह जो बहस हो रही है इतनी जल्दबाजी में है कि इस पर ही हमको लगता है कि सरकार किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेती है, जिस चीज पर जमकर बहस होनी चाहिए । ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : नहीं, तो यह हाउस का प्रोसीजर है, यह तो कालिंग अटैंशन है इसमें सरकार का क्या मामला है ।

श्री राम अवधेश सिंह : मेरा मतलब यह है कि सरकार को बिना कालिंग अटैंशन के ही इस पर बहस करानी चाहिए थी । मेरा तो यह मतलब है । लेकिन वह बहस नहीं करायी तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करके कालिंग अटैंशन के माध्यम से बहस कर रहे हैं ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Sir, it is the House and not the Government which decides which subject should be discussed in the House. It is the House which decides. The hon. Member is a part of the House. Therefore, he is equally responsible. He is unnecessarily blaming the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I have already told him. Let us not convert this into a discussion. (*Interruption*). Mr. Reddy, please sit down. Today is the penultimate day. We are already pressed for time.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, my point is that the Government should come out with a *suo motu* statement on this important issue, in regard to remunerative prices to the farmers.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Government comes out with a *suo motu* statement in case there is something to be declared in the House. I am going to make a statement today on the Kharif prices. But in regard to the discussion, it is for the House to decide.

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, कृषि राज्य मंत्री द्वारा यह जो बयान जारी किया गया है मैं तो समझता था कि यह कृषि राज्य मंत्री जी पुराने समाजवादी हैं। ...**(व्यवधान)** आपको मालूम नहीं पुराने समाजवादी रहे हैं, इसलिए इनकी दृष्टि कुछ साफ और स्पष्ट रहेगी और कम से कम निर्गुण बात नहीं बोलेंगे । लेकिन जो इनकी अंतिम पंक्ति है उसे मैं पढ़ता हूं । उससे लगता है कि इतने निर्गुण बोलेंगे समाजवादी कभी निर्गुण नहीं बोलता। लेकिन ये निर्गुण बात बोलकर सदन को और सदस्यों को गुमराह करना चाहते हैं । मैं पढ़ता हूं :

"The Government is fully alive to the needs of the farmers and spares no effort to see that they receive remunerative prices for their produce."

मतलब यह कि इसमें लगता है कि सब बातें कह दी गई हैं । हम लोग चाहते थे कि मंत्री महोदय जी कोई बाहर के नहीं हैं, यह बात को समझते हैं तो इनको कहना चाहिए कि रेम्युनरेटिव प्राइस हम कैसे दें क्योंकि प्राइस जो भी तय होती है इसमें सरकार बहुत अहम भूमिका अदा करती है । ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो खुले बाजार में, खुली प्रतियोगिता में सारी चीजें तय होती हों, ऐसी बात नहीं है ।

महोदय, आपको यह जानकारी है कि पूरी अर्थ व्यवस्था एक तालाब की तरह है । अगर तालाब में कोई एक छोटा रोड़ा डालता है तभी लहरें उठती हैं लेकिन छोटी-छोटी उठती हैं । कोई बड़ा रोड़ा डालता है तो बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं । इसलिए अर्थ व्यवस्था में कोई भी काम करेंगे चाहे सरकारी पक्ष से हो या गैर सरकारी पक्ष से हो तो उसका टोटल रिजल्ट कीमत पर आता है, जो पूरा परिणाम निकलता है वह कीमत पर जाता है ।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Sir, the concerned Minister is not here. I do not know who is taking note of what is being said.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I am here. I am sitting in the other corner of the bench.

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, किसानों को उचित कीमत मिले, इसके लिए यह जरूरी है कि सरकार केवल भाषा में यह न लिखे कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं बल्कि उसका कुछ ठोस सबूत उसको देना चाहिए । ऐसे तो आपने जो लिखा है इसमें पूरा बयान है कि फर्टिलाइज़र का दाम, पेस्टीसाइड का दाम, इरीगेशन का दाम, लेबर कौस्ट, यह सब इसमें जोड़ा हुआ है । इसको तो जोड़ा जाना चाहिए । लेकिन एक बात आप जानते हैं कि बहुत सी चीजों की कीमत खुद सरकार तय करती है वैसे तो अनाज की कीमत भी तय करती है, लेकिन जैसे फर्टिलाइज़र के दाम, पेस्टीसाइड के दाम, जो कृषि के इंस्ट्रूमेण्ट हैं उसके भी दाम सरकार तय करती है । अब यह सरकार इस बात से अपनी जवाबदेही से नहीं हट सकती कि चूंकि खुली बाजार प्रतियोगिता है, इसलिए जो दाम बाजार में तय हो जायगा, वही किसानों को मिलेगा । फर्टिलाइजर का दाम ज्यादा हो जायगा तो लाजमी है कि अनाज के दाम पर भी उसका असर पड़ेगा और उसी ढंग से डीजल का जो पानी पटाने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं, उनका दाम बढ़ जायेगा तो लाजमी है कि अनाज की कीमत बढ़ जायगी । लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो चाहते हैं कि अनाज की कीमत बढ़ाई जाये । जब तक अनाज की कीमत, खेती में पैदा होने वाली चीजों की कीमत और करखनियां सामान की कीमत में संतुलन कायम नहीं होता उचित कीमत किसान को नहीं मिल सकती है ।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 500 रुपए मन अगर गेहूं बेचिए और 500 रुपए बोरा खाद कर दीजिए तो फायदा क्या है ? आप 200 रुपए गेहूं रखिए और 50 रुपए खाद का दाम हो तो उससे किसान को फायदा है । इसी ढंग से जो डीजल का दाम आपने रखा है—साढ़े चार रुपए उसको आप कर दीजिए दो रुपए या डेढ़ रुपया और बिजली के दाम भी घटाइए । आप कारखानों के मालिकों को देंगे बिजली तो उसके दाम 30 पैसे, 40 पैसे यूनिट और खेती के लिए 60 पैसे, 70 पैसे या 90 पैसे यूनिट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रेट हैं, कोई एक रेट नहीं है । इसके लिए सरकार को चाहिए, कम से कम भारत सरकार को चाहिए कि एक अपनी ओर से सबसिडी के तौर पर, जितनी हैसियत हो सके, बिजली के दाम, डीजल के दाम पटाने के लिए जो उपयोग में आएगा वह कम से कम दाम में दिया जायेगा ।

महोदय, आपको इस बात की जानकारी होगी कि 32 डॉलर प्रति बैरल जब पेट्रोल का दाम था तब भी डीजल का दाम ढाई रुपया था और अब 12 डॉलर प्रति बैरल हो गया है अरब देशों में तो भी जो बाहर से तेल मंगाती है सरकार उसमें व्यापार करती है । एक-तिहाई से भी कम कीमत हो गयी और यहां अधिक है । कम से कम खेती के परपज़ के लिए सरकार को कम दाम पर देना चाहिए तभी सस्ता अनाज मिलेगा ।

महोदय, सरकार का मानना है कि गरीबी रेखा से नीचे 40 परसेंट लोग हैं और हम लोग तो शायद कहते हैं 60 परसेंट गरीबी रेखा के नीचे आदमी यहां हैं । चलिए अगर आपने 40 फीसदी को गरीबी रेखा के नीचे रखा है तो उनके लिए मैं यह नहीं चाहूंगा कि खाली अनाज के दाम बढ़ा दिए जाएं तो उनके चूल्हे की रही-सही आग भी बुझ जाय । यह सरकार को देखना है कि जो गरीब हैं जिनके घरों में दोनों टाइम चूल्हा नहीं जलता है, उनके घरों में दोनों टाइम चूल्हा जलाना है । इसके लिए अनाज की कीमत को बहुत ऊंचा नहीं बढ़ाना

है। लेकिन जो अनाज पैदा करने में सामग्री लगती है जिन चीजों का उसमें इस्तेमाल होता है, उनकी कीमत इस तरह रखी जाय कि वह उनको महंगा न पड़े, कपड़ा महंगा न खरीदना पड़े, केरोसिन आएल महंगा न खरीदना पड़े और खरीदना पड़े तो कोस्ट आफ प्रोडक्शन के अनुसार खरीदना पड़े। इस बात के लिए डा० राम मनोहर लोहिया ने एक सिद्धांत निरूपित किया था। उन्होंने कहा कि दाम घटाना छलावा है। दाम मत घटाओ। दाम घटाना तो कम्युनिस्ट लोगों का नारा है; दाम घटाओ आंदोलन कराओ। हम लोगों का कहना यह है कि दाम बांधो—मतलब लागत खर्च के मुत बिक आप दाम तय करो। करखनियां माल का दाम लागत खर्च से डेढ़ से अधिक किसी कीमत पर न हो। जब यह बात तय हो जाएगी – करखनियां सामान की कीमत जिस दिन बंध जाएगी फिर खेतिया सामान की लागत अपने आप घट जाएगी। जब खेत या सामान की लागत घट जाएगी तो उनको उचित मूल्य मिलेगा और उनके बच्चों को शिक्षा की भी व्यवस्था हो सकेगी और दवा-दारू की भी व्यवस्था हो सकेगी और खेतों का विकास भी हो सकता है। उनका खान-पान भी अच्छा हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी मैंने असली बात...

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : पार्लियामेंट में बोलने के लिए असली बात पहले बोलनी पड़ती है।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि औद्योगिक चीजों की कीमत एक बार बढ़ती है और घटती नहीं है, लेकिन खेतिया सामान की कीमत हर साल घटती बढ़ती है। जब किसानों के यहां सामान आ जाता है तो व्यापारी अपने स्टाक को अनाज को बाजार में डाल देते हैं मतलब कि यह सस्ता हो जाता है। फिर सस्ते अनाज को बड़े-बड़े सेठ-व्यापारी अपने यहां भर लेते हैं। जब जमा हो जाता है तो और बाजार से धीरे-धीरे निकाल लेते हैं फिर वह महंगा हो जाता है। इसलिए कि सरकार को कारगर ढंग से काम करना पड़ेगा। बाजार में आना पड़ेगा और जो सेठ व्यापारियों को छूट मिली होती है उन पर कारगर अंकुश लगाना पड़ेगा। महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार एक कांप्रेहेंसिव पालिसी बनाए। उस पर विचार करे। कोई जल्दी नहीं है कि आज या कल में ही बनाए। हम लोग जल्दीबाजी में नहीं हैं लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी में जरूर हैं क्योंकि इस समय खासकर सारे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बाढ़ से फसल बह गयी है। मैं चाहूंगा कि फसल का बीमा करने की जिम्मेदारी सरकार ले। आप इंडस्ट्रियल बीमा करा सकते हैं सारा करा सकते हैं और जो फसल बीमा है उसके बारे में सरकार बहुत दिन से कहती आ रही है। मेरी सरकार से जोरदार मांग है कि वह फसल बीमा कराए और एक कांप्रेहेंसिव पालिसी बनाए। खासकर जो कृषि उत्पादन में लगनेवाली चीजें हैं औद्योगिक चीजें हैं उनके संबंध में किसानों की और सरकार की एक मिलीजुली कमेटी होनी चाहिए ताकि वह दाम तय करने में एक अहम भूमिका अदा करे।

SHRI V. RAMANATHAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, as has been stated by many honourable Members here, this is a problem which has been agitating us for a very long time, but so far no solution has been arrived at. Every year this problem crops up and is discussed here, but the problem continues to hang fire as it has been doing for the past so many years.

Sir, the agriculturists are not getting remunerative prices for their products. Although everybody feels that agricultural economy or rural economy is the backbone of Indian economy, rural economy is not properly looked after although the agriculturists are in a majority. Agriculturists constitute 70 per cent of our population but they continue to live in the same poor condition in which they were 40, 50 or 100 years ago. Their status and standard of living has not risen during all these years whe

reas the status of people living in the cities has risen to the level of five-star hotels.

Sir, let us compare the rural economy and the five-star urban economy. Without any investment and without any labour the wealth and economy of the city people is increasing and their standard of living is rising higher and higher whereas the standard of living of people living in the rural areas is going lower and lower day by day. The condition of the rural population is such that they look to the Government for some benefits like construction of huts and petty loans of Rs. 500 or Rs. 1,000 at minimum interest for the purchase of bullocks, cows and things like that whereas the people living in the cities get lakhs and crores of rupees on loan from the banks for the construction of five-star hotels and leading a luxurious life and their standard of living is going higher and higher. If this state of affairs continues without any check, then the entire economy of this country will go down.

Sir, those who are involved in industries are flourishing whereas those who are dependent on agriculture are not able to make both ends meet. The agriculturists are in a very precarious condition. I would like to give you just one figure only. During January to March, 1987, the prices of agricultural commodities have declined by 2.4 per cent whereas the prices of industrial commodities rose by 0.9 per cent. Therefore, the prices of industrial products are going higher and higher whereas the prices of agricultural products are coming down. The agriculturists are not able to get the value for their products. Whereas the amount and cost of their inputs are rising higher and higher, they are not able to get fertilizers. The prices of pesticides, insecticides and fungicides are not fixed by the Government although fertilizers are sold at prices fixed by the Government. The prices of pesticides, insecticides and fungicides are risihg higher at great speed. This is affecting the agriculturists and, therefore, the Government must look into this problem and remedy the situation.

Sir, while the agriculturist is sinking due to all these problems, at least the State Government comes forward to help them by writing off their loans from cooperatives but when the agriculturists get some loans from the State Bank or any other nationalized bank, they are not able to get any concession from them. This aspect of the problem also the Government must consider.

Lastly, Sir, Tamil Nadu produces a lot of sugarcane and now everyone there is growing a lot of sugarcane Fortunately, though the State Government wants to put it as a lower-recovery area, it is now included in the high-recovery area. They have included it because of some problem of the people there.

Furthermore, in Tamil Nadu, crushing is possible only after December. Due to agro-seasonal conditions, the curshing can start only in the month of December, and it will proceed up to September. Up to September maximum it goes there. Therefore, if the excise duty rebate is given to the crushing factories, from the factories the agriculturists can get some benefit. In the northern parts of the country, they start crushing in the early season, and the late season goes only from March to April or May, maximum. The people in northern India who do crushing in April or May are getting heavy rebate concessions. Early crushing is possible here. But in Tamil Nadu, early crushing is not at all possible. Crushing goes up to August and September. The late-crushing rebate should be given . On three years average, there is consideration for giving rebate. That also should be taken into account. Due to shortage of water, due ro shortage of rainfall, due to shortage of crushing facilities, it is being extended. Therefore, that also should be considered.

Agriculture must be dealt with as an industry. If it is dealth with, if it is classified as an industry and all concessions are given to that industry, the economy of this country will flourish.

With this I conclude.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है यह जवाब बिल्कुल विरोधाभास से भरा हुआ है । गवर्नमेंट ने अपने जवाब में यह कहा है कि हम किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस देना चाहते हैं लेकिन दूसरे पैरे में सरकार यह कहती है कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दी है । रेम्यूनरेटिव प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक नहीं हैं । जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है । गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारण होता है वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है । रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं । अगर दोनों ही एक शब्द होते तो सरकार को दोनों शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती । आजादी के बाद किसानो क्षेत्र से किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर, वह रुपया किसानों से लूट कर औद्योगिक क्षेत्र को दे दिया है । इसीलिए जो कृषि क्षेत्र है वह सरकार के उद्योगपतियों और बडे व्यापारियों के लिए चारागाह बन गया है । अभी 1970-81 के दरमियान एक अर्थ शास्त्री ने अध्ययन किया है कृषि क्षेत्र से कितना रुपया पलायन होकर औद्योगिक क्षेत्र में जाता है और उस अध्ययन के मुताबिक 10 वर्षों के दरमियान 45 हजार करोड रुपया कृषिक्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में गया है । यह किसान की लूट है । यह लूट क्यों होती है क्योंकि सरकार रेम्युनरेटिव प्राइस तय नहीं करती है किसानों के लिए । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो नेशनल सैम्पल सर्वे कराया है 1981 में उसके मुताबिक किसानों पर कर्ज का बोझ बतहासा बढ़ता जा रहा है । 1961 में किसान के पास 1970 करोड रुपये कर्ज था और 1981 में किसान पर बोझ 5737 करोड रुपये बढ गया । यह इंगित करता है कि किसान के ऊपर तीन गुना बोझ बढ गया है । अगर किसान में क्षमता होती कर्ज देने की और अगर रेम्युनरेटिव प्राइस उसे दिया जाता है तो किसान पर यह बोझ न बढता । किसान उसको चुका देता । यह बढ़ता हुआ कर्ज इस बात का संकेत है कि किसानों को रिम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिलता है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र की आमदनी और गैर-कृषि क्षेत्र की आमदनी सन 1950 के बाद कितनी बढी है ? सन 1950-51 में कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आमदनी 396 ० थी और सन 1979-80 में यह 413 रु० हो गई । लेकिन गैर-कृषि क्षेत्र की आमदनी 632 रु० से बढकर 1151 रु० हुई । यह इस बात का संकेत है कि सरकार ने किसानों को रिम्युनरेटिव प्राइस दिया होता तो जिस रूप में गैर-कृषि क्षेत्र में लोगों की आमदनी बढकर दुगुनी हो गई है उसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी आमदनी दुगुनी अवश्य होती, लेकिन सरकार ने किसानों को सपोर्ट प्राइस दिया और इस प्रकार से किसान ठगा जाता रहा । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानी को रिम्यूनरेटिव प्राइस न देने के कारण किसानों का दरिद्रीकरण बढ़ा है, उनका इम्पालरिशमेंट बढा है इमिजराइजेशन बढ़ा है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों के दरमियान जहां सीमान्त किसान 50 प्रतिशत थे, उनकी संख्या बढकर 56 प्रतिशत हो गई और दूसरी तरफ सन् 1970 और 1980 के बीच में खेत मजदूरों की संख्या 26 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है । यह इस बात का संकेत है कि अगर किसानों को रिम्युनरेटिव प्राइस दिया जाता तो किसानों का इम्पावरिशमेंट और इमिजरा जेशन नहीं होता । इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने जो कृषि मूल्यों के संबंध में दस्तावेज दिया है, उसमें आपने जो नीति निर्धारित की है, जिसमें आपने कहा है कि किसानों को समर्थन मल्य और रिम्युनरेटिव प्राइस मिलना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य और रिम्युनरेटिव प्राइस में फर्क क्या है ? क्या मैं इसका अर्थ यह समझूं कि किसानों को सरकार ने जो

रिम्युनरेटिव प्राइस दिया है, वह वह प्राइस नहीं है ? क्या सरकार लाभप्रद कीमत की परिभाषा करेगी ताकि किसानों को वह मिल सके ? अगर सरकार हम से पूछे तो मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी प्राइजेज के बारे में बात बताई गई है, लाभप्रद कीमत का अर्थ यह है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन के साथ-साथ किसानों को इतनी आमदनी होनी चाहिए कि वे वाजिब जिन्दगी बशर कर सकें, वह उनको मिलनी चाहिए । इस बात की और आपके वक्तव्य में संकेत नहीं किया गया है ।

दूसरी बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने चुनावों के दौरान, सन् 1984-85 में जो चुनाव हुए थे, उनके दौरान, कहा था कि औद्योगिक मूल्यों और कृषि मूल्यों के बीच में समता लायेंगे । आज क्या प्राइस है ? कृषि मूल्यों का आंकड़ा, प्राइस इंडेक्स 309.8 है और औद्योगिक मूल्यों का आंकड़ा 339.8 प्रतिशत है यानी 10 प्रतिशत का अन्तर है । क्या यही समता है ? आर्थिक समीक्षा 1985-86 यह कहती है कि कृषि मूल्यों और औद्योगिक मूल्यों में 10 प्रतिशत का अन्तर है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कि क्या इन दोनों कीमतों के बीच में वे समता लायेंगे ? सरकार ने अपने वक्तव्य में कृषि मूल्यों में कहा है कि टर्म्स आफ ट्रेड किसानों के खिलाफ जाएगा तो हम उसका डजस्टमेंट करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि अभी टर्म्स आफ ट्रेड क्या है ? टर्म्स आफ ट्रेड का प्राइस किसानों का 286.5 है । किसान जो प्राइस पे करता है, वह 304.5 है । आप कहेंगे कि आपने यह कहां से लिया । मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका जो यह एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है, एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्राइस कमीशन है उसकी जो 1985-86 की रिपोर्ट है, उसकी आप देखिये । उसमें लिखा हुआ है कि टर्म्स आफ ट्रेड किसानों के खिलाफ चला गया । अगर किसान को मिलते हैं 286 तो वह पे करता है 304.5 यानी 12 प्रतिशत का अन्तर है । इस तरह किसान के टर्म्स आफ ट्रेड में 12 प्रतिशत का अंतर है और यह अंतर अरबों किसानों से छीनकर उद्योगों को दे दिया जाता है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या सरकार टर्म्स आफ ट्रेड जो किसानों के खिलाफ चला गया है, उनके विपरीत चला गया है, उसको ठीक करेगी ?

चौथी बात जो मैं सरकार से कहना चाहता हूं वह यह है कि 1970-71 में धान का मूल्य था 55 पये, गेहूं का मूल्य था 70 पये । 1986 में धान की कीमत हुई 146 पये और गेहूं की कीमत हुई 162 पये । थोक मूल्य कितना बढ़ा ? अगर 1970-71 वर्ष का सूचकांक 100 माना जाय तो उसके आधार पर सम समय थोक मूल्य 402 है । इसका मतलब यह है कि थोक मूल्य चार गुना बढ़ा है । लेकिन किसानों की कीमत बढ़ी है केवल 25 प्रतिशत यानी ई गुना । थोक मूल्यों की कीमत बढ़ी चार गुना और किसान का जो समर्थन मूल्य बढ़ा वह बढ़ा ढाई गुना । क्या सरकार इसको जस्टिफाई करेगी ? जो थोक मूल्य बढ़ा उसी हिसाब से किसानों का प्राइस भी तय होना चाहिए था ।

अन्त में एक बात मैं कहना चाहूंगा और वह यह है कि पंजाब में गेहूं और धान की पैदावार 30 क्विंटल है, बिहार में 10 क्विंटल है, यू० पी० में 16 क्विंटल है, महाराष्ट्र में 7 क्विंटल है । जब कि सरकार पूरे देश के लिए क प्राइस तय करती है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार डिफरेंशियल प्राइस किसानों के लिए तय करेगी ? जिस प्रकार से प्रोडक्शन में अंतर है उसी तरह से क्या डिफरेंशियल प्राइस तय करेगी सरकार द्वारा कहा गया कि ऐसी संभावना नहीं है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चीनी के डिफरेंशियल प्राइस, सीमेंट के डिफरेंशियल प्राइस आयरन और स्टील के डिफरेंशियल प्राइस, खाद के डिफरेंशियल प्राइस, जब इतनी चीजों के डिफरेंशियल प्राइस हो सकते हैं तो कृषि के, किसान द्वारा उत्पादित जो चीजें हैं उनके डिफरेंशियल प्राइस क्यों नहीं हो सकते ? पंजाब के किसान के लिए जो समर्थन मूल्य तय होता है वह उसके लिए लाभकारी हो सकता है । लेकिन वह यू० पी० के किसान के लिए, बिहार के किसान

[श्री सूरज प्रसाद]

के लिए, बंगाल के किसान के लिए, महाराष्ट्र के किसान के लिए तथा दूसरे किसानों के लिए लाभकारी नहीं है इस लिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उसके डिफरेंसियल प्राइस तय करेगी ?

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि रूई और जूट देश में एक बहुत ही शोषण की चीज बन गई है । महाराष्ट्र, में रूई की मोनोपली परचेज है लेकिन और राज्यों में रुई की मोनोपली परचेज नहीं है । जूट की कहीं भी मोनोपली परचेज नहीं है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार रुई और जूट की मोनोपली परचेज देश के पैमाने पर लागू करेगी ? धन्यवाद ।

SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I would like to congratulate Mr. Kalpnath Rai for realising the helplessness of the farmers. One of our learned friends and an eminent parliamentarian, Mr. M. S. Gurupadaswamy told that this problem has been existing right from the inception of both the Houses of Parliament but the time allowed is very little and the subject is very vast. Keeping that in mind, I would like to express my views on this. I would like to question the concerned Minister that if an industrialist is allowed to fix his product's rates, including all his charges, overhead charges, taxes and profits, that what prevented the farmer to fix his own price for his produce? What is the conspiracy behind it?

It is admitted that about 2.00 P.M. seventy-five per cent of the people of our country depend upon agriculture. Seventy-five per cent of the people have adopted agriculture as their profession. And for the last forty years, no farmer is happy with his own profession. The hon. Minister said that remunerative prices are paid to the farmer on the advice of the Agricultural Prices Commission, I have the feeling that for a long time that Commission never consisted of a farmer as its member. Do the people in the Commission have technical knowledge about agricultural produce? The cost of cultivation nowadays has gone so high that the price paid to the farmer is not at all coordinating with it, not to speak of the price being remunerative or profitable. The other day, one scientist, in a meeting connected with a paddy nursery, was telling that rice was got directly. That was the practical knowledge of a scientist of this country and we are relying on such scientists. Another agronomist was telling in another meeting that after the harvest of groundnut, the stubbles have to be removed. Where is the question of removing stubbles in the case of groundnut? That means, our scientists have only theoretical knowledge and they do not have any practical knowledge. How will these people pay remunerative prices to the farmer? The price is low whether it is paddy or cotton or sugar or chilli. At the same time, see the scale of balance when the farmer goes to the bank. Is he given the proper finance when he hypothecates huge landed property? No.

In this context, I want to point out that if there is coordination among the Ministries of Agriculture, Irrigation and Forests, it will be good to the farmer. The other day in a meeting it was said that for the last sixteen years a project is pending completion in the State of Maharashtra. Had there been proper coordination between the Agriculture Ministry and the Irrigation Ministry, clearance for the project would have been given long back. There should be some give and take between the Ministries. After all, we are all Indians and it known to everybody. Let anybody benefit out of it.

At the present moment, we are passing through a crisis throughout the country. Some parts of the country are facing floods. Some other parts are in the grip of drought. At this hour, the coordination among Ministries which I mentioned earlier assumes greater importance.

The other day, the Textiles Minister was telling that the Government are importing cotton and synthetic granules. Why? Are they not available in this country? Is jute not available? What made you import the synthetic granules and cotton? Nobody is there to look after the farmer. The day will come when the farmer will rise in revolt. Then Governments as this cannot exist. So many Members of this House are coming from farmer community. But I am sorry to say, the position of the farmer is the same for the past forty years. He is faced with the same problems. We must be ashamed. I do not know whether the Price Commission is writing the fate of our farmers. Let the Commission be practical. Let them calculate the cost of cultivation and give the farmer his due. Why is the Government not ensuring enough irrigation facilities to the farmer? Water is the main input for agriculture. Why don't you make a proper calculation of the remunerative price to the farmer? Why cannot you guarantee supply of water for irrigation? We have so many rivers—the Brahmaputra, the Ganga, the Kaveri, the Godavari, the Krishna, and so on. Most of the river water is going waste. Even after 40 years of independence nobody in authority seems to be worried about it. Our entire nation is dependent on irrigation and we as a nation can survive only when we can tap our irrigation potential to the maximum. Most of us are from villages. We are representing the poor villagers. They are looking up to us; more than 50 crore people are looking up to us for amelioration of their conditions; they are looking up to us in the hope that we will free them from the domination and exploitation by the industrialists, the monopolists, the capitalists. I give you a couple of small examples. A kg of tobacco is bought at Rs. 5 or 6. From out of that kg. of tobacco you know how may hundreds of packets of cigarettes are made and sold and the percentage of profit earned by the industry. And what is it you are paying to the farmer who has grown that kg of tobacco? Similarly you get a kg. of cotton for Rs. 5 or Rs. 6 from out of which a pair of dhoties are made and sold for not less than Rs. 100. What is the profit to the industrialist in this at this rate? And what does the farmer get? Nobody seems to be interested in analysing these factors. So I demand there should be a meaningful discussion in the House on this subject. I request the honourable Minister to take these aspects into consideration and ensure that justice is done to farmers. Thank you.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I do not want to take much time of the House. It is rather curious to see that honourable Members belonging to the ruling party are also interested in ensuring a remunerative price to the peasantry for their produce. They know the art of creating an illusion among the peasantry. I want to remind them that those days are gone and of late the peasantry is getting more and more disillusioned about the mockery of Congress-I. At the outset I want to say categorically that denial of remunerative price to the peasants for their produce is not an isolated phenomenon. It has to be viewed in the backdrop of the economy and the taxation policy which is pursued by the Goverment at the Centre. The denial of remunerative price to the peasants for their produce is to be viewed in the backdrop of the general growing crises of our country which engulf all spheres of our life and which arose not from the heavens but from out of the very economic and taxation policies, the policy of deficit financing, the policy of increasing the burdens, the policy of wooing

[Shri Ramnarayan Goswami]

multinationals in our country, the policy of letting loose the monopolists, the speculators, to loot our people. So I must vent in this august House the general feeling of our peasantry that the Congress-I at the Centre is determined to pass the burden of the crises on to the shoulders of the peasants.

Denial of remunerative prices to the farmers is a part of the game. Mr. Vice-Chairman, Sir, a few days ago—I cannot remember the exact date—perhaps on Monday last, in reply to the debate on the Essential Comodities (Amendment) Bill, the Food and Civil Supplies Minister was compelled to admit that the Government failed to hold the price line. Rapid increase in the prices of all the essential commodities is the general phenomenon of our country. Now, Sir, I want to know one thing from my friends sitting on the opposite side. Who are the victims of this price hike? It is common knowledge that the peasants who constitute 60 per cent of our population are the victims of the price hike in all the essential commodities. They are force to bear the burden arising out of the high prices of essential commodities and agricultural inputs. Who is responsible for such price hikes? It is the Government at the Centre here, and you cannot deny that. It is not merely the industrialists and the cunning businessmen who are increasing the prices of essential commodities, but it is the Government also which increases the prices. The Government itself, by issuing administrative orders, is hiking the prices. So, you cannot shirk your responsibility for this sordid picture which is there in our country and I say that the economic policy that is pursued by the Government and the resultant price hike in respect of all the essential commodities are at the dictation of the World Bank and the IMF.

Sir, in these days of sky-rocketing prices, we are demanding State trading in at least fourteen essential commodities to keep the prices at the level of the purchasing capacity of the poor peasantry. But this demand has all through been denied by the Government. The terms of trade, as you know, between the agricultural and industrial products are very much unfavourable to the peasantry. The peasants are forced to buy agricultural inputs at higher prices while they are at the same time, forced to sell their produce at a very low price . . . (*Time bell rings*) . . . So, we demand remunerative prices for cash crops such as jute, sugarcane, cotton, tobacco, coconut, rubber etc. and for goodgrains also. Sir, you are quite well aware of the fact that there is no pority between the finished goods's prices and the prices of the raw materials required for the production of those goods. May I ask the honourable Minister whether there is any parity, whether there is any relationship, between the price of jute and the prices of jute goods? Is there any relationship between the price of cotton and the price of cloth? Is there any relationship between the price of rubber and the price of motor tyres? There is no relationship at all and there is no parity at all. The prices of agricultural products are so fixed by the Government and are so recommended by the CACP that they hardly meet even the cost of production. Not only that, Sir. Apart from this, there is hardly any proper mechanism to purchase the agricultural products from the peasants. There is no mechanism at all. I do not want to take much of the time of the House. You know the problem of jute and you know the cost of of production of jute and you also know what the

jute growers are facing now. The JCI has completely refused to purchase their produce. Not only the high prices of essential commodities and agricultural inputs, but also the natural calamities, affect our peasants and especially this year these have affected them very much. So, for all this we demand remunerative price and urge upon the Government to ensure it.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the valuable and convincing recommendations made by other speakers before me about the unremunerative prices being given to the farmers. The greater sufferers are the small farmers. The bigger farmers have the ability to weather unfavourable conditions. They are caught in a mesh because they have no mobility. They are wedded to the land and they cannot leave it and go out to take up anything else. What has really been happening is that in the last few years they have been getting lesser and lesser value for their input, especially for the land and their own human labour. Also you find that more and more farmers are finding it difficult to pay back their loans.

Now, I come to this years' drought. I think it is going to ruin many farmers. I would particularly like to stress the case of Punjab. Now, Punjab provides something like 50 per cent of the rice stock to the Centre. Last year, it was able to give something like 45 lakh tonnes of rice to the Centre's stock. This year, they don't expect the overall crop to be more than 50 lakh tonnes as opposed to 75 lakh tonnes of last year. So, their contribution to the Centre's reserves would be not more than 22 to 25 lakh tonnes. Apart from other inputs, this year to irrigate the land has become a major problem, especially for those fields which have got to be irrigated by electric or diesel pumps. Since the water level has gone down, they find that a three-HP motor is not enough. They are using five-HP or eight-HP pumps. As far as the diesel-run pumps are concerned, apart from having to use similarly, larger engines, the price of diesel works out, in the overall, something like 15 times more than the electricity. Unless the support price is substantially increased this year, the farmers, I feel, will not be able to get out of the present drought in any healthy form. It will be a tremendous setback for the Punjab farmers if the support price is not raised. I have been working this out and I think that the minimum support price they need is Rs. 200|- per quintal. Otherwise he will go more under debt. This will also add to his inability to take advantage of the next crop. He will not be able to take advantage of the next crop if there is rain by that time. I would like to make one more recommendation. I understand that the Centre had laid down for the millers last year to sell at Rs. 264|- per quintal. The State agencies could sell at Rs. 297|- per quintal. The result is that the poor farmer gets much less money from the millers than what he can get from the State agencies. I think there is a good reason to increase the price to the millers so that the farmers can get more. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Matto. Last speaker.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very

[Shri Ghulam Rasool Matto]

much for providing me an opportunity to speak. I congratulate Shri Kalpnath Rai though he belongs to the ruling party—he should ordinarily keep quiet—he takes up almost invariably in every session the cause of the farmers and the remunerative price to be paid to the farmers.

Mr. Vice-Chairman, Sir, many people have spoken about this thing here. The hon. Minister has made a very important announcement in his statement and I would like to ask him whether it can be really implemented. He said: "The recommendations on procurement/minimum support prices are made by the Commission for Agricultural Costs and Prices keeping in view a number of factors, such as, the cost of production of crops, changes in input prices, inter-crop price variations, changes in the 'terms of trade' between agricultural and non-agricultural sectors, general economic conditions prevailing in the country, etc." I would like to ask the hon. Minister one small point. If you are not able to help the farmers, they will really leave the farming profession. I tell you this about the farmers in Kashmir also. Many farmers there want that their children should have white-collared jobs rather than go to farming. I would like him to tell the Commission for Agricultural Costs and Prices one thing. If I take 1950 as the base year, what was the price of vegetables and other essential commodities like edible, milk, sugar, pulses oil and other things at that time, what was the price of wheat and rice at that time, what is the position now? If the rise in prices of vegetables, milk, edible oil and other things is more than 400 to 600 per cent why is it that the price of wheat and rice—it was Re. 1 at that time a kg.— has been increased by only 50 per cent? This thing has to be taken into consideration by tht Agricultural Costs and Prices Commission because the cost of inputs has gone up. Mr. Aurora was saying just now about the cost of electricity. He said that because of drought, the water table has gone down and they have to use now 7½ to 10 HP engines instead of 3 HP engines to draw water tubewells. These things are to be taken into consideration. I would request the hon. Minister to take up this thing A.C.P.C. (*Time bell rings*) Sir, there is no doubt that the hon. Minister has taken into consideration the factor of the consumer lobby. There is no doubt about it. My only point is that unless we give incentives to the farmers, they will run away, they will not be able to produce the wheat and rice required for the country. I would like to ask the hon. Ministers, in this connection, two questions. I have read reports and I would like him to tell us whether it is a fact that first-class variety of moong was imported by us from China at a CIF price of Rs. 4. Its price is not less than Rs. 9 or Rs. 10 here in retail. I understand that he has recommended a levy of 25 per cent as customs duty on that. And I would like him to throw a little light on this point which is very important in connection with discussion on remunerative prices to farmers. My second point is that there has been a crusade of war between the Minister of Textiles and the Minister of Petro-chemicals only two days back. We had a discussion for about three hours when the Minister of Textiles was here championing the cause of jute growers wherein I had also said that the jute growers must be helped and all that. Then came the Minister of Industry (Department of Petro-chemicals) championing the cause of the HDPE people. The Agriculture Ministry is the burgomaster of this whole affair. They have to sit in judgment whether in the interest of the jute growers, they have got to do away with the HDPE lobby and help the jute growers or not? This he must assert and unless he asserts himself the position of the jute farmers is

going to be bad. (*Time bell rings*) Sir, my last point is with regard to the crop pattern. Does the hon. Minister have an exercise made in each district and each taluka for the purpose of helping the farmers? They should advise on the crop pattern so that the farmers can get a remunerative price. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Yes, Mr. Minister.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (MAHARASHTRA): Sir, just please give me one minute.

SHRI VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No, no. (*Interruptions*)

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Sir, I want just to mention only one thing. It is very important Agricultural commodities are purchased by the NAFED: While fixing the prices are they taking into consideration the cost of production of agricultural produce?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, in my statement I have mentioned about the objectives of the price policy of agricultural produce. The main objectives is to provide remunerative prices to our agriculturists for his products. But, at the same time, we have to strike a balance between the prices, for the producer and the prices which are to be paid by the consumer. So, in striking a balance we take care of both the sides, that is of the producer as well as of the consumer. And we try to do justice to both sides. It is not correct to say that no justice is done to the farmers If we look to the pricing pattern right from the appointment of the Agricultural Prices Commission in January 1965 and later on Commission for Agricultural Costs and Prices from March 1985, you will see a sea-change in the price pattern. The prices are always increased because the food prices have gone up, because the terms of trade have to be made favourable to the farmers and that is why a number of things are taken into consideration. Sir, the Commission takes into consideration the need to provide incentive to the producer, that is the first term of the terms of reference of CACP. They need to provide incentive to the producer for adopting improved technology and for maximising production. The need to ensure rational utilisation of land, water and other production resources and the likely effect of the price policy on the rest of the economy particularly on the cost of living, level of wages, industrial cost structure. Now these are the criteria which are kept in mind while fixing the agricultural prices. So, basically they take cost into consideration. Now this cost is not haphazardly arrived at. There is a set procedure and accordingly the cost of agricultural produce is calculated.

Sir, there is a scheme, comprehensive scheme, for studying the cost of cultivation. This is operated by the universities and agricultural universities. A field man is appointed to look after 10 holdings in each selected village and 9,000 such holdings are looked after by this field man who takes record of everything which the farmer consumes and which the farmer utilises, the agricultural inputs as well as other products which he consumes. And then the cost is arrived. And this cost is based on the methodology and sampling procedure fixed by eminent economists in agricultural universities. So, it is done very scientifically and while fixing the support price by SACP a number of items are taken into consideration like cost of production, changes in input prices, input-output price parity, trends in market prices, demand and supply, intercrop price parity, effect of industrial cost structure, effect of general price level, effect of cost of living, international market price situation, parity between prices paid and prices received etc., and after taking all these into consi-

[Shri Yogendra Makwana]

deration, we come to the final figure. In this, not only the cost of inputs is taken into consideration but also the cost of human labour, including the family labour of the farmer is taken into consideration. One hon. Member— I think it was Mr. Aurora— while speaking said that the value of the human labour, particularly that of the farmer is not properly taken into consideration. This is not correct because we do not take the minimum wages fixed by the State Government, but take wages actually paid by the farmes while calculating the cost. The prevalent wage is also taken into consideration while evaluating the family labour.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप 8 घंटे का लगाते हैं, लेकिन किसान तो 24 घंटे खेत में रखवाली करता है, उसमें काम करता है। आप इसका 8 घंटे का ज्यादा जकी का लगाते हैं।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: मैंने हिसाब लगाया है, हिसाब लगाने वालों ने भी लगाया है

So, in all the 16 States the field workers is there are located at the rate of one field worker per cluster of 3 villages. There are number of clusters for collecting the data. I have got a list with me; but I do not want to bore the Members with this list, because when I say it is the 16 States which are covered, it means almost the entire country is covered.

SHRI KALPNATH RAI: We want to know it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: In Andhra, there are 60 clusters; Assam, the number is 45; Bihar- 60; Gujarat 60; Haryana-30; Himachal-30; Karnataka-45; Kerala-30; M.P.-60; Maharashtra-60; Orissa-45; Punjab-30; Rajasthan-60; Tamil Nadu-60; U.P.-75; West Bengal-60, and Andhra Pradesh Special study, it is 30.

There are the centres where the field man is appointed who takes particulars of prices paid by the farmer and communicates it to the agricultural university, general university so that they can arrive at the correct cost. Not only this, the Commission takes into consideration the human labour, hired human labour, value of owned bullock labour, value of hired bullock labour, hire charges of machinery, value of own machinery, value of seeds, both farm produced and purchased, value of insecticides and pesticides, value of manure, own and purchased, value of chemicals and fertilizers, then depreciation of implements and farm buildings, irrigation charges revenue of land, cesses and other taxes, interest on working capital miscellaneous expenses, payment to artisans, etc. All these are taken into consideration while fixing the procurement support prices.

The hon. Member says that the terms of trade are not favourable to the farmers. An example was given by one hon. Member to prove that it is not in fovour of the farmer. Yes, if you see it on the face of it; it looks like that. I have got the table from 1979-80 to 1984-85. This is how the terms of trade worked. Prices received by the farmers and prices paid by the farmers. In 1979-80, it was 100, that is both equal. In 1980-81, it was -1.5. *(Interruptions)*

SHRI SURAJ PRASAD: You are quoting wrong figures.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I am quoting from authentic records. *(Interruptions)*

In 1981-82, it was -7. In 1982-83, it was -4.4. 1983-84 +0.1 and 1984-85 -0.3. As against this, let us look at the productivity index of all crops because it should be compared both ways. In 1979-80, it was 100. In 1980-81, +14. 1981-82, +16.7. 1982-83, +14.7. 1983-84, +31 and 1984-85, +33.0. Now, the marginal loss in the prices paid and received is made good by the

productivity index. In terms of trade, the loss is marginal; the farmer is losing marginally. But he is gaining on account of the increase in productivity. Why this increase in productivity? What made the farmers get more yield? Not because of his own labour alone. Not because of good monsoon alone. But also because of a number of factors, number of measures which the Government have taken. Increase in the irrigation facilities providing new techiques, research done on new seeds which are high-yielding, resistance to drought, resistance to pests and diseases etc. These are all factors which have contributed. Now, when the Government spends money on research and other things, the benefit should go to the average citizen in this country, not to a section of the society only. It should be evenly distributed. The benefit should go evenly to all sections of the society.

SHRI KALPNATH RAI: The consumer.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It should go to the consumer also as it should go to the farmer.

SHRI KALAPNATH RAI: Tell me how?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: In deciding the price, this is is taken into consideration. There, the farmer is not a loser. He is benefited. I will come to the points made by each hon. Member. It is wrong to say that the terms of trade are not in favour of the farmer.

Now, the first speaker, Shri Kalpanath Rai, wanted that agriculture should be treated as an industry. It is not possible. If it is done, it will not be to the advantage of the farmers. (*Interruptions*) It will not be in their interest. I can spend hours with the hon. Members to explain this, but the House will not permit. I say, it will not be in the interest of the farmers. There are millions of farmers. As against this, industries are specific in number. Not only that. There is a mixture of subsistence household in the case of farmers as against commercial activity of industries in specified areas. They can discontinue their production when they came to know that the prices are going to fall because of the law of demand and supply. They can discontinue production and they can create artificial shortage. By this, they can get more prices. It is not possible in the case of a farmer. He cannot discontinue in the middle of it. Once he has sown, he has to go further. Therefore, it is not possible for the farmers to stop in between. This is possible in the case of an industry. Control of production is not in the hands of the farmers.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरियाणा): मिनिस्टर साहब क्या किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): इनको पूरा करने दीजिये।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: There is heterogenety of products. A large variety of products is there. In cotton also there are a number of varietits, not one and these varieties make it difficult to declare agriculture as industry. Then the nature of the agricultural product is perishable as against the industrial product. Then there are a number of factors but I do not want to take much time of the House, it is not in favour of the farmers and, therefore, Government is not declaring agriculture as industry.

Then the hon. Member said that it is not remunerative according to the terms of the trade. Sir, I can just discuss the terms of the trade, the price paid and the price received

[Shri Yogendra Makwana]

by the farmers. I have got a list of products which the farmers are consuming and for which he pays. He has to pay on items like cycles, paper and paper products, tanned and finished leather, tobacco, textiles; drugs and medicines, cosmetics, soap and detergents, metal products; utensils edible oils, sugar, salt, kerosene, matches; electricity coal services, and for intermediate consumption, fertilizer, services and repairs; electricity, insecticides, diesel, oil cakes, drugs and medicine and for capital formation, cement, lime; transporting equipment, machinery and machine tools, iron and steel, ferro alloys, logs and timber; agriculture fowrah and things like that. These are the commodities which the farmer consumes. So, the field official takes into account the price of these commodities, he prepares a chart and sends it to the university. The commodities for which the prices are received by the farmers are: cereals, pulses, oilseeds; milk and milk products, meat and meat products, fruits, vegetables gur and then tobacco, sugarcane etc. These are the commodities which are sold by the farmers and on which I have just given to the hon. Members the difference between the prices paid and the prices received. And ultimately, it goes to the benefit of the farmers.

The hon. Member wanted to now the CACP was formed or when it will be formed. Sir, the Government of India appointed the Agriculture Prices Commission in January 1965, Then there was a demand from the peoples' representatives Members of Parliament, representatives of the farmers, and on their demand in March, 1985 the Government renamed the Commission as the Commission for Agricultural Costs and Prices. From March 1980 the terms of trade were also included. This Commission is looking into the cost of the agricultural produce and then fixes the price. (*Interruptions*) I am coming to it one by one.

The hon. Member wanted to know how many members will be there. There will be 7 members. One will be Chairman, another will be member-secretary, then there will be two members from eminent economists and there will be three members representing the farmers, they will be the representatives of the farmers. Earlier there were only three membrs, one chairman, one member-secretary and one member. Now it is seven. Now about the farmers' representatives—those three members—we have had a lot of discussion on it. One point of view was that it should be from North, South, East and West. Another viewpoint was that it should be from large farmers, medium farmers and small and marginal farmers. Then there was another point of view that agricultural labour's representative should be taken into this Commission. Then there was another point of view that the agro-climatic zones should be represented. All these views are conflicting. We received a number of suggestions from Members of Parliament, from the State Governments, from the MLAs and a number of other interested parties, including the farmers' organisations. Now these suggestions we have to process and find out the suitable members. Now that exercise is done and it will be declared within a very short period of time.

SHRI KALPNATH RAI: When?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: That is impossible to say, because I have to....

SHRI KALPNATH RAI: Prime Minister said in 1984 that it would be constituted. Now it is 1987.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: So far as Agriculture Ministry is concerned, we have done the exercise and we will declare it as early as possible.

SHRI KALPNATH RAI: Upto what time?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I said, minimum possible, shortest possible.

SHRI KALPNATH RAI: How much?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Shortest means shortest.

SHRI KALPNATH RAI: How much? Two months, three months, twelve months.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It cannot be definite, the hon. Member should understand.

SHRI KALPNATH RAI: Sir, he has to say how many months he will take. For four years it has gone on.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I cannot say anything. It is not within my control. I can say about things which are within my control. A number of formalities have to be done. I will tell you later on.

SHRI KALPNATH RAI: Tell me the date.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: So far as Agriculture Ministry is concerned, we have sent it.

SHRI KALPNATH RAI: In how many days, you tell me, will it be possible? How many months?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It is not possible to say. I can say within the shortest possible time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): That is all. You cannot insist upon it like that.

श्री कल्पनाथ राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रधान मंत्री जी ने दिसम्बर, 1984 में कहा कि एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन बनेगा । 1985 में श्री बरा सिंह ने कहा कि एक महीने के अन्दर बन जाएगा । 1986 में कहा कि विद न बन मंथ बन जाएगा । यह 1987 है। चार साल हो गए लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन नहीं बना है । यह कब बनेगा यह मैं पूछना चाहता हूं ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, will you allow this debate in between, or will you allow me to continue my reply? I have already said, within the shortest possible time.

SHRI KALPNATH RAI: What is "shortest"?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I will say that it will be declared as early as possible. I myself will try for it.

SHRI KALPNATH RAI: Will it be in this session or before the next session?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I cannot guarantee anything.

SHRI KALPNATH RAI: Why? You are the Minister for Agriculture.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): You can say efforts will be made.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: That is what I said: I will do it as early as possible. I cannot say before the session. I cannot say that.

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: You don't tell in how many days, you don't tell in how many months. What is this?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Months if you want I can tell you. I can say that before the next session I will declare. Not during this session, but before the next session, I will.

SHRI KALPNATH RAI: Thank you very much.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I will do it before that. Don't worry. Then, Sir, hon. Shri Vikal wanted to know the names. He will know when we declare it. Another point which he raised was also about terms of trade, what the farmers are paying is more than what they are receiving.

Shri Jagdambi Prasad Yadav wanted to know how many representatives there will be. I have said that there will be three. I just informed the honourable Members as to how the data are collected by the field workers and how the cost is decided and how the price is fixed. So, I have already replied to him.

There is one point that he has made. It seems there is a lot of confusion in his mind when he says I promised that Members of Parliament will be consulted. I never said it. I said that the Commission is consulting every body who goes to them. The farmers' representatives have also met them. Even Members of Parliament, if they want to meet them and express their opinion, they can very well meet them and express their opinion. That is what I have said... (*Interruptions*) ...They get the opinion of the State Governments, they get the opion of the farmers' representatives, they get the opinion of the people's representatives like MLAs and MPs. Those who want and those who are interested can go to the Commission and give their opinion and discuss with them.

Then he says that water, electricity and fertilizers should be provided to the farmers. There are various schemes under which the inputs are provided to the farmers. About electricity, the State Governments are providing electricity at subsidized rates. I do not know about the rates of electricity of the different State Governments. But, so far as we are concerned, the Government of India is creating irrigation potential. Sir, we have 64 million hectares under irrigation at present and in the Seventh Plan the allocation, as I said earlier, is about 40 times more than what it was in the First Five-Year Plan. Therefore, there is a constant effort on the part of the Government of India to provide irrigation facilities to the farmers.

Then, crop planning is a conflicting issue. An honourable Member says that there should be regional prices. If we have regional prices, there can never be specialization of a particular area for a particular crop, because our farmers are traditional and they are in the habit of growing traditional crops only even though it is not remunerative, even though the yield is low. Even though the other crop can give more yield, they go in for the traditional crops only. In order to encourage them, if there is a national price policy on agriculture, then we can take the major areas. Particularly when we talk of major areas, we take major areas like Andhra Pradesh or States like Punjab and Haryana who grow paddy. Similarly, in the case of wheat, cereals, oilseeds and pulses, we go by the areas. So, from the major growing areas we collect the information on costs and then the prices are decided. So, our effort is to make it scientific, our effort is to reduce the cost of production, so that the farmer can get more by way of prices.

Shri Ram Awadheshji said so many things. He said that crop insurance should be there. It is already there. But it is voluntary and it is for the State Governments to accept it or not. But most of the States have now accepted crop insurance and the minimum unit they have accepted is district, except Andhra Pradesh which has declared *mandal* as the unit.

SHRI JAGESH DESAI: Is it throughout the country?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The majority of the States have accepted crop insurance. Maharashtra also has accepted.

Then Shri Suraj Prasad says that the Government is not giving remunerative prices but support prices.

SHRI KALPNATH RAI: All big points.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Yes. He says that the support price should be at remunerative level. It is support and support is at a remunerative level, not at bare minimum level. So, the price is supported at a remunerative level for the farmers. He wanted to know about the terms of trade. I have already said about that. About regional price also I have replied.

Shri Ramnarayan Goswami said there is no State trading. Particularly the communist Members want state interference everywhere. We have state trading. But that is for foreign trade, not for internal trade. For the agricultural produce we have the NAFED, the Food Corporation of India, the Cotton Corporation of India, the Jute Corporation of India. All these corporations enter into purchase and sale of agricultural produce. So, there is no necessity of creating another State Trading Corporation for agricultural produce.

Then, Sir, Mr. Matto, the last speaker, wanted that the base year should be 1950 for the consumer-price index which is prepared by the Labour Ministry, the Bureau of Labour, for industrial workers and agricultural labour. They also reconstruct it at intervals, and when they reconstruct, they take that as the base year. When I gave the terms-of-trade figures the base year is 1979-80. That is the base year we have taken, and it is not possible to take 1950 as the base year.

Then, he wanted to know about the import of moong. That is not my subject. It is the Commerce Ministry which does it.

These are the points which the hon. Members raised about agricultural prices.

Hon. Member, Shri Gurupadaswamy, mentioned about the India Committee on Netherlands. He mentioned about the propaganda carried out by the campaign manifesto. Particularly he mentioned about it. This is an organisation of extreme left wing of a Marxist group, and they have a lot of misunderstanding in their mind. They say that India is run by monopoly capital. That is what they believe. Therefore, they say that whatever aid is provided to India goes to capitalists and that, therefore, the milk should not be provided, that is, the SMP and butter milk should not be given. We do not know about their linkages in India. But we came to know about an advertisement given by M/s. Hindustan Levers Ltd. So, we wrote to them. M/s. Hindustan Levers Ltd. say, and I would like to quote two, three sentences from the letter:

> "We have checked up with our associates in Netherlands and have been informed that the ICN is an organisation which publishes papers containing inaccurate and misleading information. This is born out also in the publication referred to by you in which factually incorrect information has been included also about our company."

They, further, they say that this is an organisation with which they have no connection, and it is an organisation which cannot be taken seriously. This is what they have said. But the Government of India is enquiring into it. Our Embassy is constantly advising us on the activities of this organisation.

But one hon. Member earlier mentioned that there is a deep game behind it, that there are some interested parties who wanted to preach their religion, that they may be playing a role behind it and that that is why they are after our Operation Flood Programme.

This is what I wanted to inform the hon. Members, through you. I am very much thankful to you for giving

[Shri Yogendra Makwana]

me this much time. Thank you very much.

SHRI JAGESH DESAI: Sir, a small question.

SHRI RAM CHANDRA VIKAL: Sir....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No. Statement by the Minister.

3.00 P.M.

—CONTD.

STATEMENT BY MINISTER

II. Procurement prices in respect of Paddy and Kharif coarse cereals for the 1987-88 marketing season fixed by the Government.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Government have fixed the procurement prices for paddy and kharif coarse cereals for the 1987-88 marketing season. The procurement price of all varieties of paddy in common group of fair average quality has been raised from Rs. 146 per quintal during the 1986-87 marketing season to Rs. 150 per quintal for the 1987-88 marketing season.

For fine variety of paddy, the price will be Rs. 154 per quintal and for super fine variety of paddy Rs. 158 per quintal during the 1987-88 marketing season.

The Government have also fixed the procurement prices for jowar, bajra, maize and ragi each of fair average quality at Rs. 135 per quintal for the 1987-88 marketing season.

SOME HON. MEMBERS: Very ridiculous increase.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Sir, I am asking a question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You have to wait for your turn. We have started clarifications only. Now Mr. Ramnarayan Goswami.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): Sir, I want to seek some clarifications from the Minister. Firstly, may I know from the Minister on what basis he has fixed the procurement prices? Secondly, while fixing the prices, whether he has taken into consideration....

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I have not heard you. Will you please repeat?

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: May I know from the Minister on what basis he has fixed the procurement prices? Secondly, while fixing the procurement prices, whether he has taken into consideration the natural calamities like floods and drought which are prevailing in our country.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, while fixing the procurement prices...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You can react finally after all the clarifications are sought by the hon. Members.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Sir, may I know from the Minister whether he has taken into account apart from C.A.C.P. recommendations, the "terms of trade" which has been frequently referred to during the Calling Attention Notice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Sir, the Government has raised the price of paddy in common group from Rs. 146 per quintal during the 1986-87 marketing season to Rs. 150 per quintal for the 1987-88 marketing season, and for